

रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान विकट वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सुव्यवस्थित वित्तीय बाजार की स्थिति सुनिश्चित की। इसने भागीदारी को व्यापक बनाने, पहुंच को आसान बनाने और उत्पाद नवोन्मेष को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विनियामकीय फ्रेमवर्क को मजबूत करके वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों को विकसित और व्यापक बनाने के प्रयासों को जारी रखा। व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने और अनुपालन बोझ को कम करने के उपाय विदेशी मुद्रा से संबंधित विभिन्न विनियमों की निरंतर समीक्षा और पुनर्गठन की प्रक्रिया का परिणाम थे। मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के साथ चलनिधि परिचालन को सक्रिय रूप से तदनु रूप किया गया।

V.1 वर्ष 2022-23 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने सक्रिय रूप से और उभरती चुनौतियों के जवाब में नई विनियामक पहलों को लाना जारी रखा ताकि पहुंच को आसान बनाने, भागीदारी को व्यापक बनाने, अनुपालन बोझ को कम करने और बाजार पारदर्शिता बढ़ाने के संदर्भ में वित्तीय बाजारों को और विकसित किया जा सके। अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के खिलाफ लक्षित उपाय वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमों का संज्ञान लेते हुए पेश किए गए थे। चलनिधि प्रबंध परिचालन मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के अनुकूल थे अर्थात्, नीति रेपो दर के सख्त होते चक्र में समायोजन की क्रमिक वापसी। रिज़र्व बैंक ने बाह्य व्यापार और भुगतान को भी सुगम बनाया और विदेशी मुद्रा बाजारों के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा दिया, ताकि व्यापार करने में और आसानी हो सके और प्रक्रियाओं की आवधिक समीक्षा और यौक्तिकीकरण और नियामक अनुपालन प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए निदेशित प्रयासों के माध्यम से अनुपालन बोझ को कम किया जा सके।

V.2 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को चार खंडों में बांटा गया है। वित्तीय बाजारों के विकास और विनियमन को खंड 2 में शामिल किया गया है। खंड 3 में रिज़र्व बैंक के बाजार परिचालन पर चर्चा की गई है। खंड 4 में, बाह्य व्यापार और भुगतान और उदारीकरण और बाह्य वित्तीय प्रवाह के विकास से संबंधित उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अंतिम खंड में निष्कर्ष दिया गया है।

### 2. वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)

V.3 वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) को मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), ब्याज दर व्युत्पन्नी, विदेशी मुद्रा और ऋण व्युत्पन्नी बाजारों के विकास, विनियमन और निगरानी का काम सौंपा गया है। विभाग ने 2022-23 के लिए निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस अधिदेश के अनुसरण में कई उपाय किए।

#### वर्ष 2022-23 के लिए कार्यसूची

V.4 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- 2022-23 की पहली छमाही में भारत में गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्नी (एनसीसीडी) के लिए सीमाओं में भिन्नता की आवश्यकताओं को शुरू करने के लिए निदेश जारी करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ V.5]; और
- अधिक उत्पाद नवोन्मेष की अनुमति देने, घरेलू बाजार में अनिवासी पहुंच को आसान बनाने और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से जनता से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा करने के बाद 2022-23 में रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (आईआरडी) पर संशोधित निदेश जारी करना (पैराग्राफ V. 6)।

### कार्यान्वयन की स्थिति

V.5 एनसीसीडी के लिए भिन्नता मार्जिन<sup>1</sup> (वीएम) के आदान-प्रदान पर निर्देश 1 जून 2022 को जारी किए गए थे। विभाग ने एनसीसीडी के लिए प्रारंभिक मार्जिन के आदान-प्रदान को अनिवार्य करते हुए मसौदा निदेश भी जारी किए।

V.6 विभाग संशोधित आईआरडी निदेशों को लागू करने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण अपना रहा है। पहले चरण के रूप में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 10 (1) के तहत अधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 (एडी कैट-1) बैंकों और एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को गैर-निवासियों और अन्य पात्र बाजार निर्माताओं को विदेशी मुद्रा निपटान – एकदिवसीय सूचकांक स्वैप (एफसीएस-ओआईएस) अनुबंधों की पेशकश करने की अनुमति दी गई है।

### प्रमुख पहल

अनधिकृत विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) व्यापार प्लेटफॉर्मों पर कार्रवाई

V.7 भारतीय निवासियों को विदेशी मुद्रा व्यापार सुविधाओं की पेशकश करने वाले अनधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों के बढ़ते

प्रसार के मद्देनजर, एक चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें निवासियों को अनधिकृत व्यक्तियों से या अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। इस संबंध में विदेशी मुद्रा लेनदेन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक सेट भी प्रकाशित किया गया था, जिसमें अधिकृत ईटीपी की एक सूची और अनधिकृत संस्थाओं की एक 'चेतावनी सूची' भी थी, जिन्हें विदेशी मुद्रा व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला समझा जाता है। अनधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों पर लेन-देन में शामिल जोखिमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 'आरबीआई कहता है' कार्यक्रम के तत्वावधान में एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है (बॉक्स V.1)।

गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्नी (एनसीसीडीएस) के लिए मार्जिन आवश्यकताएं

V.8 ओवर द काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्नी बाजारों की आघातसहनीयता को मजबूत करने और ओटीसी व्युत्पन्नी पर जी -20 सिफारिशों की पृष्ठभूमि में, मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (भिन्नता मार्जिन) निदेश, 2022 दिनांक 1 जून 2022 को जारी किए गए थे। निदेश गैर-केंद्रीय रूप से स्वीकृत

### बॉक्स V.1

#### अनधिकृत विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म

भारत में विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) लेनदेन फेमा, 1999 और उसके तहत जारी नियमों, विनियमों, निर्देशों और अनुमतियों के तहत होते हैं। मौजूदा वैधानिक और विनियामकीय फ्रेमवर्क के अनुसार, भारत में निवासी व्यक्ति केवल अनुमेय चालू और पूंजीगत खाता लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा खरीद / बेच सकते हैं; और केवल अधिकृत व्यक्तियों (मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों सहित) से। जबकि अनुमत विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित किए जा सकते हैं, वे केवल रिज़र्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों पर या रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विनियमों और शर्तों के अनुसार मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर किए जाने चाहिए।

हाल के वर्षों में देश में अनधिकृत ईटीपी का प्रसार हुआ है जो निवासियों को विदेशी मुद्रा व्यापार सुविधाओं की पेशकश करता है। इन प्लेटफॉर्मों

का विज्ञापन बड़े पैमाने पर समाचार प्लेटफॉर्मों, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर किया जाता है, जिसमें सर्च इंजन, ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म और गेमिंग एप्प शामिल हैं और उनके भ्रामक विज्ञापन अक्सर असंगत / अत्यधिक प्रतिलाभ, प्रारंभिक निवेश पर बोनस और सुनिश्चित पुरस्कार के वादे के माध्यम से भोले-भाले ग्राहकों को लक्षित करते हैं। ऐसी भी रिपोर्टें आई हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म उन एजेंटों को शामिल करते हैं जो विदेशी मुद्रा व्यापार / निवेश योजनाओं को शुरू करने के लिए संभावित ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं।

ये प्लेटफॉर्म रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत नहीं हैं और इन पर किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन फेमा, 1999 का उल्लंघन करते हैं। ऐसे अनधिकृत

(जारी..)

<sup>1</sup> जी-20 ओवर द काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्नी बाजार सुधारों के संदर्भ में, ओटीसी व्युत्पन्नी जिन्हें केंद्रीय रूप से मंजूरी नहीं दी गई है, उन्हें भिन्नता मार्जिन (प्रतिपक्षकार के बीच वर्तमान बाजार-से बाजार एक्सपोजर को प्रतिबिंबित करने के लिए एकत्र या भुगतान किए गए संपार्श्विक) और प्रारंभिक मार्जिन (संभावित भविष्य के जोखिम को कवर करने के लिए एकत्र किए गए संपार्श्विक) की आवश्यकताओं के अधीन होना चाहिए।

प्लेटफार्मों में कम प्रबुद्ध ग्राहकों को आकर्षित करने और उन्हें वित्तीय नुकसान होने का जोखिम होता है।

### विनियामकीय पहलें

इस बाजार गतिविधि और व्यक्तियों के आर्थिक नुकसान और इन प्लेटफार्मों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टों के बारे में बढ़ती शिकायतों का संज्ञान लेते हुए, 3 फरवरी 2022, 7 सितंबर, 2022 और 10 फरवरी 2023 को चेतावनी जारी की गई थी। जनता को आगाह किया गया था कि वे अनधिकृत ईटीपी पर विदेशी मुद्रा लेनदेन न करें या इस तरह के अनधिकृत लेनदेन के लिए पैसे जमा न करें। यह स्पष्ट किया गया कि फेमा के तहत अनुमति प्राप्त उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए या रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत नहीं की गई ईटीपी पर विदेशी मुद्रा लेनदेन करने वाले निवासी व्यक्तियों पर फेमा के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

अधिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, उन संस्थाओं की एक 'चेतावनी सूची' प्रकाशित की गई थी, जो न तो फेमा अधिनियम, 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं और न ही

विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए ईटीपी संचालित करने के लिए अधिकृत हैं। चेतावनी सूची में उन संस्थाओं/प्लेटफार्मों/वेबसाइटों के नाम भी शामिल हैं जो अनधिकृत संस्थाओं/ईटीपी को बढ़ावा देते प्रतीत होते हैं, जिनमें ऐसी अनधिकृत संस्थाओं के विज्ञापनों के माध्यम से या प्रशिक्षण/सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का दावा करना शामिल है। 'चेतावनी सूची' संपूर्ण नहीं है और यह रिजर्व बैंक के प्रकाशन के समय उसके पास उपलब्ध सूचना पर आधारित है। यह स्पष्ट किया गया है कि सूची में शामिल नहीं होने वाली इकाई को रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति/ईटीपी की प्राधिकार स्थिति का पता लगाने के लिए, जनता अधिकृत व्यक्तियों की सूची और अधिकृत ईटीपी की सूची का संदर्भ ले सकती है, जिसे रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। इन उपायों के पूरक के रूप में, जनता को सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक सेट भी प्रकाशित किया गया है।

स्रोत: आरबीआई.

ओटीसी व्युत्पन्नी लेनदेन के प्रतिपक्षों के बीच भिन्नता मार्जिन के आदान-प्रदान को अनिवार्य करते हैं। निदेशों का दायरा ब्याज दर, विदेशी मुद्रा और क्रेडिट व्युत्पन्नी लेनदेन तक फैला हुआ है और ओटीसी व्युत्पन्नी बाजारों में उनके बकाया लेनदेन के आधार पर वित्तीय और गैर-वित्तीय संस्थाओं के लिए लागू होगा।

*सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए 'पूर्ण सुलभ मार्ग' – अतिरिक्त निर्दिष्ट प्रतिभूतियां*

V.9 30 मार्च 2020 को शुरू किए गए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) में अनिवासी निवेश के लिए पूर्ण सुलभ मार्ग (एफएआर) गैर-निवासियों को कुछ विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों (5-वर्ष, 10-वर्ष और 30-वर्ष के जी-सेक जारी करना) में बिना किसी समष्टि-विवेकपूर्ण सीमा के निवेश करने की अनुमति देता है। एफएआर के तहत अनिवासी निवेशकों द्वारा निवेश के लिए उपलब्ध जी-सेक के विकल्प बढ़ाने और सॉवरेन प्रतिफल वक्र में चलनिधि बढ़ाने के उद्देश्य से, 7-वर्ष और 14-वर्षीय अवधि के जी-सेक के सभी नए निर्गम (वर्तमान निर्गम सहित) को 7 जुलाई 2022 को एफएआर के तहत विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में शामिल किया गया था। 7 और 14 वर्ष की प्रतिभूतियों के साथ एफएआर की इस वृद्धि को एफपीआई द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त

किया गया है, जैसा कि 8 जुलाई, 2022 से एफपीआई धारिता के निर्माण से संकेत मिलता है। सात वर्षीय प्रतिभूतियों में एफपीआई की हिस्सेदारी एफएआर के तहत शामिल होने से पहले 118 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2023 को 7,084 करोड़ रुपये हो गई। इसी अवधि के दौरान 14-वर्षीय प्रतिभूति में 36 करोड़ रुपये से 1,313 करोड़ रुपये तक का निर्माण देखा गया।

*विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश - छूट*

V.10 मध्यावधि के फ्रेमवर्क (एमटीएफ) के तहत, सरकारी और कॉर्पोरेट ऋण में एफपीआई निवेश कुछ समष्टि-विवेकपूर्ण सीमाओं के अधीन हैं, जैसे, (i) एक अल्पकालिक सीमा की आवश्यकता जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉण्ड में प्रत्येक में 30 प्रतिशत से अधिक निवेश की एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता नहीं हो सकती है, और (ii) न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता आवश्यकता जिसमें एफपीआई कम से कम एक वर्ष की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ केवल कॉर्पोरेट ऋण लिखतों में निवेश कर सकते हैं। समग्र समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से,

सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट ऋण में एफपीआई द्वारा निवेश को 7 जुलाई 2022 को 31 अक्टूबर 2022 तक अल्पकालिक सीमा और न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता की आवश्यकताओं से छूट दी गई थी। उपरोक्त अवधि के दौरान, एफपीआई ने वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) में 3,955 करोड़ रुपये का निवेश किया।

*प्राधिकृत डीलर श्रेणी I (एडी कैट-1) बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा उधार*

V.11 उधारकर्ताओं के एक बड़े समूह द्वारा विदेशी मुद्रा उधार लेने की सुविधा के लिए, जिन्हें विदेशी बाजारों तक सीधे पहुंचने में मुश्किल हो सकती है, एडी कैट-1 बैंकों को 7 जुलाई 2022 को विदेशी मुद्रा उधार (ओएफसीबी) का उपयोग अंतिम उपयोग उद्देश्यों के लिए संस्थाओं को विदेशी मुद्रा में उधार देने की अनुमति दी गई थी, जो बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए निर्धारित नकारात्मक सूची के अधीन है। इस तरह की उधारी जुटाने की व्यवस्था 31 अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध थी।

*एकल प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी) को विदेशी मुद्रा वाले व्युत्पन्नी बाजार में सौदा करने की अनुमति देना*

V.12 भारत में बैंकों को फरवरी 2022 में गैर-निवासियों और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ एक विदेशी मुद्रा वाले दिवसीय सूचकांक स्वैप (एफसीएस -ओआईएस) में लेनदेन करने की अनुमति दी गई थी। चूंकि एसपीडी भी देशीय ओआईएस बाजार में बैंकों की तरह बाजार निर्माता हैं, फेमा, 1999 की धारा 10 (1) के तहत अधिकृत एसपीडी को 8 अगस्त 2022 से गैर-निवासियों और अन्य पात्र बाजार निर्माताओं के साथ एफसीएस-ओआईएस लेनदेन करने की अनुमति दी गई थी।

*महत्वपूर्ण बेंचमार्क की अधिसूचना*

V.13 वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019 के तहत प्रदान की गई आवश्यकताओं के संदर्भ में, रिज़र्व बैंक ने मुंबई अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा प्रस्तावित दर (एमआईएफओआर) को 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के रूप में अधिसूचित किया था।

एमआईएफओआर एक वित्तीय बेंचमार्क है जिसमें शामिल हैं: (i) यूएसडी लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (एलआईबीओआर) और (ii) यूएसडी/आईएनआर फॉरवर्ड प्रीमिया घटक के रूप में। 1 जनवरी 2022 से एलआईबीओआर की समाप्ति की शुरुआत की पृष्ठभूमि में, यूएसडी एलआईबीओआर से जुड़े लेनदेन को अब केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुमति दी गई है। 1 जनवरी 2022 से नए वित्तीय लेनदेन के लिए एमआईएफओआर को संशोधित एमआईएफओआर (एमएमआईएफओआर) के साथ बदल दिया गया है। एमएमआईएफओआर में समायोजित सुरक्षित एकदिवसीय वित्तीय दर (एसओएफआर) और वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) फॉरवर्ड प्रीमिया दर शामिल है। एमएमआईएफओआर को दिसंबर 2022 से 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के रूप में अधिसूचित किया गया है।

*विदेशी बाजारों में स्वर्ण मूल्य जोखिम बचाव*

V.14 भारत में निवासी संस्थाओं को विदेशी बाजारों में स्वर्ण मूल्य जोखिम के लिए अपने निवेश के बचाव करने की अनुमति नहीं थी। इन इकाइयों को अपने स्वर्ण एक्सपोजर के मूल्य जोखिम को कुशलतापूर्वक बचाने के लिए अधिक आघातसहनीयता प्रदान करने के लिए, निवासी संस्थाओं को (12 दिसंबर 2022 से) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर अपने स्वर्ण कीमत को जोखिम से बचाने की अनुमति दी गई है, जिसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

*एफएआर के तहत सॉवरेन हरित बॉण्ड का समावेशन*

V.15 गैर-निवासियों को अप्रैल 2020 से एफएआर के तहत बिना किसी प्रतिबंध के जी-सेक की विनिर्दिष्ट श्रेणियों में निवेश करने की अनुमति दी गई थी। एफएआर के तहत विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूची का विस्तार 23 जनवरी 2023 को किया गया था ताकि इसमें 2022-23 में सरकार द्वारा जारी सभी सॉवरेन हरित बॉण्ड शामिल किए जा सकें।

### 2023-24 के लिए कार्यसूची

V.16 वर्ष 2023-24 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- एनसीसीडी के लिए प्रारंभिक मार्जिन के आदान-प्रदान को अनिवार्य करने वाले मसौदा निदेश 16 जून 2022 को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किए गए थे। अंतिम निदेश 2023-24 में जारी किए जाएंगे (उत्कर्ष 2.0);
- परिचालन क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से, छोटे विदेशी मुद्रा (एफएक्स) एक्सपोजर वाले उपयोगकर्ताओं के लिए विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी बाजार तक पहुंच को आसान बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता वाले ग्राहकों का एक व्यापक समूह अपने बचाव कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए आघात सहनीयता से लैस है, एफएक्स जोखिमों की बचाव के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा 2023-24 में की जाएगी; और
- बाजार पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से, 2023-24 में व्यापार रिपोर्टिंग (टीआर) की रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण फ्रेमवर्क की समीक्षा की जाएगी (उत्कर्ष 2.0)।

### 3. वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.17 वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी) मुख्य रूप से वित्तीय बाजारों में मौद्रिक नीति संचरण के पहले चरण को सुरक्षित करने और देशीय और विदेशी दोनों बाजार परिचालनों के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति के रुख के साथ संरेखण में चलनिधि प्रबंधन परिचालन के संचालन के लिए जिम्मेदार है।

### 2022-23 की कार्यसूची

V.18 वर्ष के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप, सभी उपलब्ध चलनिधि प्रबंधन साधनों का उपयोग करके चलनिधि प्रबंधन परिचालन को प्रभावी ढंग से पूरा करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ V.19];
- यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए प्रभावी तरीके से विदेशी मुद्रा परिचालन जारी रखना (पैराग्राफ V.20-V.21); और
- वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान करना (पैराग्राफ V.22)।

### कार्यान्वयन की स्थिति

#### मुद्रा बाजार और चलनिधि प्रबंधन <sup>2</sup>

V.19 2022-23 के दौरान, रिजर्व बैंक ने समायोजन वापस लेने की दिशा में मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के मद्देनजर सक्रिय रूप से चलनिधि विकसित करने में कामयाबी हासिल की। फरवरी से अप्रैल 2023 के दौरान दीर्घकालिक रेपो परिचालन (एलटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) के निर्धारित मोचन के मद्देनजर, यह चलनिधि प्रबंधन के प्रति अपने दृष्टिकोण में लचीला रहा। रिजर्व बैंक ने चलनिधि की स्थिति के आधार पर एलएएफ के दोनों ओर परिचालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहा, अर्थात् परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) और परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) परिचालन। नीतिगत दरों में वृद्धि के साथ-साथ वर्ष के दौरान नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में वृद्धि के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से प्राथमिक चलनिधि के अवशोषण के कारण भारित औसत कॉल मुद्रा दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - अप्रैल

<sup>2</sup> चलनिधि प्रबंधन परिचालनों से संबंधित ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय III में दिए गए हैं।

2022 में 3.47 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2023 में 6.50 प्रतिशत हो गया।

### विदेशी मुद्रा बाजार

V.20 अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त किए जाने और अमेरिकी खजाना प्रतिफल में वृद्धि से डॉलर में निरंतर वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान रुपये में मूल्यहास के साथ कारोबार हुआ। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और घरेलू पूंजी बाजारों से एफपीआई की निकासी से भी रुपये पर दबाव रहा। वित्तीय वर्ष के दौरान ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें औसतन लगभग

95 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थीं, जबकि पिछले पांच वर्षों में औसतन लगभग 63 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी। तथापि, एफपीआई के बहिर्वाह में कमी आई क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने अमेरिका में मुद्रास्फीति के चरम पर पहुंचने के संकेतों के बीच सख्ती में कमी कर दी।

V.21 रिज़र्व बैंक ने बाजार की स्थिति को व्यवस्थित बनाए रखने और विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए देशी/विदेशी ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा व्युत्पन्नी (ईटीसीडी) खंडों में परिचालन के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया (बॉक्स V.2)।

### बॉक्स V.2

#### आईएनआर अस्थिरता को रोकने में रिज़र्व बैंक के उपायों की प्रभावशीलता

कई दशकों की उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास में प्रमुख प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों द्वारा इसके मौद्रिक नीति सख्त किए जाने के कारण 2022 में उभरती और साथ ही विकसित अर्थव्यवस्था (ईई) मुद्राओं में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। विशेष रूप से, यूएस फेड की आक्रामक नीतिगत दर वृद्धि के कारण अमेरिकी वित्तीय स्थितियों में सख्ती आई। ईएमई में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) का प्रवाह नकारात्मक हो गया, जो जोखिम-बचाव धारणा को दर्शाता है, जिससे उनकी विनिमय दर पर तेज गिरावट का दबाव पड़ा।

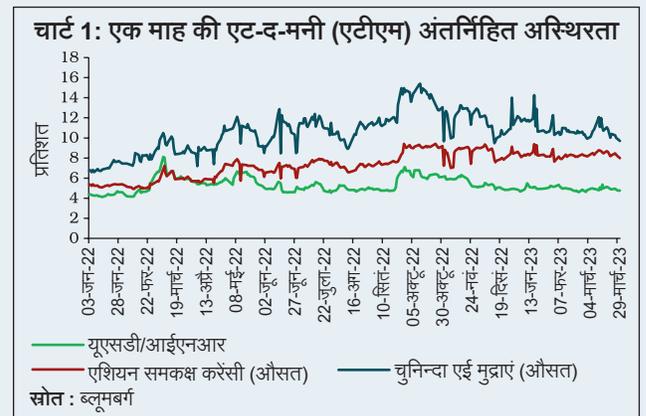
कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और इक्विटी में एफपीआई की रिकॉर्ड निकासी से भारतीय रुपया दबाव में आ गया। भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के बाद ब्रेंट के 139 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बढ़ने के बाद मार्च 2022 में अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये की अस्थिरता 8.0 प्रतिशत से ऊपर बढ़ गई। अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले लगातार नौ महीनों में घरेलू इक्विटी में एफपीआई बहिर्वाह देखा गया, जो कुल 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें जून 2022 में 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का दूसरा सबसे अधिक मासिक बहिर्वाह दर्ज किया गया। इन वैश्विक चुनौतियों और अत्यधिक अनिश्चितता के बीच, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न अन्य नीतिगत उपायों<sup>3</sup> के अलावा विनिमय दर के किसी विशिष्ट स्तर या बैंड के संदर्भ के बिना रुपये की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया।

जनवरी 2022 से मार्च 2023 के दौरान प्रमुख एशियाई समकक्षी मुद्राओं<sup>4</sup> के साथ-साथ चुनिंदा ईई मुद्राओं की औसत अंतर्निहित अस्थिरता के साथ यूएसडी/आईएनआर अस्थिरता की प्रवृत्ति बढ़ी (चार्ट 1)। रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप उपायों के बाद रुपये की अंतर्निहित अस्थिरता काफी हद

तक नियंत्रित थी और यह एशियाई प्रतिस्पर्धियों और ईई मुद्राओं के औसत से काफी नीचे रही।

भारतीय रुपये की अस्थिरता को कम करने में रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की नमूना अवधि के लिए चुनिंदा चर पर एक सामान्यीकृत स्वतः प्रतिगमन सशर्त विषमविसरिता (जीआर्क) मॉडल लागू किया गया है। यहां, निर्भर चर  $\ln r_t$ , लगातार दो दिनों में बंद दिन यूएसडी/आईएनआर स्पॉट विनिमय दर (एस) का लॉग अंतर है, जो विनिमय दर पर प्रतिगमन को दर्शाता है।

$$\ln r_t = 100 \times (\ln S_t - \ln S_{t-1}) \quad \dots(1)$$



(जारी..)

3 चीनी युआन, इंडोनेशियाई रुपिया, कोरियाई वोन, मलेशियाई रिंगिट, फिलीपीन पेसो और थाई बहत

4 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, कनाडाई डॉलर, यूरो, जापानी येन, न्यूजीलैंड डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग

यहां,  $(\Omega_{-1})$  सकारात्मक (नकारात्मक)  $\ln r_t$  अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्यहास (मूल्य वृद्धि) को इंगित करता है। यूएसडी/आईएनआर प्रतिलाभ इसके पिछले मूल्यों और एक त्रुटि शब्द ( $\varepsilon_t$ ) से प्रभावित होता है जो विनिमय दर को प्रभावित करने वाले आघातों को दर्शाता है।

$$\ln r_t = \beta_0 + \beta_1 \ln r_{t-1} + \varepsilon_t \quad \dots(2)$$

त्रुटि शब्द  $\varepsilon_t$  अंतराल की जानकारी का एक प्रकार्य है (इसके अलावा,  $\varepsilon_t$  सामान्य रूप से शून्य माध्य और इसके विचरण ( $h_t$ ) के साथ वितरित माना जाता है (इस प्रकार परिभाषित किया गया है):

$$\varepsilon_t | \Omega_{-1} \sim N(0, h_t) \quad \dots(3)$$

विचरण समीकरण ( $h_t$ ) निम्नानुसार है:

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 h_{t-1} + \gamma |\alpha_3 \text{Intv}_t + \alpha_4 \text{FII}_{\text{Equity}(t-2)} + \alpha_5 \text{Brent}_t| \quad \dots(4)$$

यहां  $\alpha_1$  और  $\alpha_2$  क्रमशः स्वतः प्रतिगमन सशर्त विषमविसारिता (आर्क) और जीआर्क शब्दों के गुणांक हैं।  $\text{Intv}_t$  रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप है,  $\text{FII}_{\text{Equity}}$  विदेशी इक्विटी प्रवाह है<sup>5</sup>, और  $\text{Brent}_t$  कच्चे तेल की कीमतें हैं।

अनुमानित मॉडल के अवशिष्ट समाधान कोई आर्क प्रभाव नहीं दिखाते हैं जो अवशिष्ट में कोई स्व-सहसंबंध नहीं दर्शाते हैं।

परिणामों से संकेत मिलता है कि रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप यूएसडी/आईएनआर अस्थिरता को कम करने में प्रभावी था, जबकि विदेशी इक्विटी बहिर्वाह में उच्च भिन्नता और उच्च ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों

### सारणी 1: जीएआरसीएच (1,1) अनुमान परिणाम

(नमूना अवधि: अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक)

चर	गुणांक	z-सांख्यिकीय	संभाव्यता
निर्भर चर: $\ln r_t$			
सी	0.053***	3.73	0.01
$\ln r_{(t-1)}$	-0.10	-1.38	0.16
विचरण समीकरण:			
$h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 h_{t-1} + \gamma  \alpha_3 \text{Intv}_t + \alpha_4 \text{FII}_{\text{Equity}(t-2)} + \alpha_5 \text{Brent}_t $			
सी	0.045***	6.29	0.00
एआरसीएच <sub>-1</sub>	0.53***	4.69	0.00
जीएआरसीएच <sub>-1</sub>	0.20**	2.41	0.01
$\text{Intv}_t$	-0.0227***	-3.60	0.00
$\text{FII}_{\text{Equity}(t-2)}$	0.000036**	2.33	0.01
$\text{Brent}_t$	0.0014**	2.41	0.01
लॉग-संभावना	-26.96	कुल अवलोकन	266
उबिन-वाटसन स्टेट	1.93	अकाकी जानकारी मानदंड	0.26
		एआरसीएच (एलएम)	0.56 (0.45)

\*\*\*, \*\* और \* क्रमशः 1 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्व स्तर को इंगित करते हैं।

स्रोत: आरबीआई कर्मचारी की गणना।

के कारण यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर में अस्थिरता बढ़ गई (सारणी1)।

### अनुसंधान / विश्लेषणात्मक अध्ययन

V.22 विभाग ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव सहित कई सामयिक मुद्दों पर विश्लेषणात्मक अनुसंधान किया।

### 2023-24 के लिए कार्यसूची

V.23 वर्ष 2023-24 के दौरान, विभाग की निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना है:

- मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप, सभी उपलब्ध साधनों के माध्यम से चलनिधि प्रबंधन परिचालन को प्रभावी ढंग से करना;
- यूएसडी /आईएनआर विनिमय दर में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए प्रभावी तरीके से विदेशी

मुद्रा परिचालन जारी रखना; और

- वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान और विश्लेषण जारी रखना ताकि निरंतर आधार पर बाजार परिचालन कार्यनीतियों का मार्गदर्शन किया जा सके (उत्कर्ष 2.0)।

### 4. विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी)

V.24 विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) का कार्य बाह्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और सरल लेकिन व्यापक, समय-सुसंगत और सिद्धांत-आधारित नीतियों को तैयार करके विदेशी मुद्रा बाजारों के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है। उल्लिखित अधिदेश को आगे बढ़ाने और फेमा को कारगर बनाने के विभाग के मिशन को जारी रखते हुए,

<sup>5</sup> इस अवधि में ज्यादातर भारतीय बाजार से निवल बहिर्वाह होता है।

जिसमें वर्तमान व्यापार और आर्थिक परिदृश्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए विनियामक फ्रेमवर्क को संरेखित करना शामिल है, विभाग ने व्यापार को और सुगम बनाने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा है। इस संबंध में, विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा जारी नए ओआई नियमों के पूरक के लिए नए विनियम और निर्देश जारी करके विदेशी निवेश (ओआई) व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किया; फेमा के तहत सभी रिपोर्टिंग देरी के लिए विलंब जमा शुल्क (एलएसएफ) फ्रेमवर्क का विस्तार किया; और विदेशी वित्त पोषण के स्रोत में विविधता लाने और विस्तार करने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) दिशानिर्देशों को उदार बनाया। इसके अलावा, निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने और भारतीय रुपये (आईएनआर ) में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करने के लिए, आईएनआर में निर्यात और आयात के चालान, भुगतान और निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था भी विभाग द्वारा की गई है।

### 2022-23 की कार्यसूची

V.25 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- समान विषयों के मौजूदा विनियमों को समेकित करके फेमा विनियमों को युक्तिसंगत बनाना जारी रखना, संशोधन अधिसूचनाओं को बार-बार जारी करना और अधिसूचनाओं/विनियमों में परिभाषाओं को संरेखित करना (पैराग्राफ V.26);
- फेमा 1999 के तहत उल्लंघनों के शमन के लिए संशोधित गणना मैट्रिक्स का कार्यान्वयन (उत्कर्ष) [पैराग्राफ V.27];
- योजना में विभिन्न मुद्दों और विसंगतियों को दूर करने के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) की व्यापक समीक्षा (पैराग्राफ V.28);
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर विनियामकीय अनुपालन के लिए विभिन्न प्रतिलाभ प्रस्तुत करने

की प्रक्रिया के स्वचालन को जारी रखना (पैराग्राफ V.29);

- निरंतर आधार पर जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन और डिजिटल सामग्री का निर्माण (उत्कर्ष) [पैराग्राफ V.30]; और
- नीतिगत परिवर्तनों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए एडी बैंकों और क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) को अधिक शक्तियां सौंपना जारी रखना (पैराग्राफ V.31)।

### कार्यान्वयन की स्थिति

*कंपाउंडिंग कार्यवाही नियमों को तर्कसंगत बनाना*

V.26 मौजूदा विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2000 का स्थान लेने के लिए एक तर्कसंगत मसौदा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2022 भारत सरकार को भेज दिया गया है। नियमों में निहित प्रावधानों को अधिनियम में निहित प्रावधानों के साथ संरेखित करने के अलावा, मसौदा नियम निम्नलिखित प्रमुख संशोधनों का प्रस्ताव करते हैं:

- कंपाउंडिंग प्राधिकरण के रूप में नामित आरबीआई अधिकारियों की कंपाउंडिंग शक्तियों को बढ़ाना।
- कंपाउंडिंग एप्लीकेशन शुल्क और कंपाउंडिंग राशि के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक /ऑनलाइन मोड को सक्षम करना; और
- कंपाउंडिंग के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए रिजर्व बैंक को शक्तियां सक्षम करना।

*फेमा, 1999, के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए संशोधित संगणना मैट्रिक्स का कार्यान्वयन*

V.27 कंपाउंडिंग राशि की गणना के लिए गणना मैट्रिक्स पर मौजूदा मार्गदर्शन नोट की समीक्षा के बाद, एक संशोधित मैट्रिक्स, जो कंपाउंडिंग राशि की गणना के लिए सरलीकृत और मानकीकृत मार्गदर्शन प्रदान करता है, अंतिम रूप देने के एक उन्नत चरण में है।

*उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) की व्यापक समीक्षा*

V.28 एलआरएस के तहत, अधिकृत डीलर (एडी) किसी भी अनुमत चालू या पूंजी खाता लेनदेन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में निवासी व्यक्तियों द्वारा 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक मुक्त रूप से प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। योजना के तहत विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक समीक्षा की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कानूनी फ्रेमवर्क, वार्षिक सीमा, अनुमत उद्देश्यों और योजना के तहत प्रत्यावर्तन आवश्यकताओं को शामिल किया गया है और एक संशोधित एलआरएस नियत समय में जारी किया जाएगा।

*विभिन्न विवरणियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का स्वचालन – विवरणियों को बंद करना/विलय/ऑनलाइन प्रस्तुत करना*

V.29 18 फरवरी 2022 को मौजूदा 65 विनियामक पेपर-आधारित विवरणियां को ऑनलाइन विवरणियां में बदलने या बंद/विलय या रूपांतरण से संबंधित विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर, अधिकृत व्यक्तियों (एपी) को इक्कीस (21) विवरणियां के ऑनलाइन जमा में रूपांतरण के बारे में अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, एक (1) विवरणियां, अर्थात् 'अनिवासी संस्थाओं से ली गई और मंगाई गई गारंटी पर तिमाही विवरणियां' को बंद/विलय कर दिया गया है। इसके बाद, एडी बैंकों को जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही से उक्त विवरणियां को बंद करने के बारे में सूचित किया गया था। ऑनलाइन प्रतिमाह में यह रूपांतरण सटीकता, गति और डेटा जमा करने की गुणवत्ता और व्यापार में आसानी में सुधार करते हुए रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए विनियामक अनुपालन की लागत को कम करने में मदद करेगा।

*जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और डिजिटल सामग्री का निर्माण करना*

V.30 क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) केंद्रीय कार्यालय में विनियमों के सरलीकरण में सहायता के लिए विभिन्न

कार्यशालाओं का आयोजन करते रहे हैं। वर्ष के दौरान एपी और फेमा प्रदर्शनी-सह-टाउनहॉल कार्यक्रमों के लिए कार्यशालाएं, जहां व्यापार और उद्योग निकाय और विदेशी मुद्रा के उपयोगकर्ता प्रतिभागी थे, आरओ द्वारा हालिया नीतिगत परिवर्तनों की व्याख्या करने और जमीनी स्तर के कार्यान्वयन के मुद्दों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, तर्कसंगत विदेशी निवेश (ओआई) नियम/विनियम जारी करने के अनुसरण में एडी बैंकों और नई ओआई व्यवस्था के तहत देरी से जमा शुल्क (एलएसएफ) आवेदनों को संसाधित करने के लिए नामित आरओ और एडी बैंकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं। उपरोक्त के अलावा, मास्टर निदेशों, प्रशिक्षण मॉड्यूल और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के माध्यम से विभिन्न दिशानिर्देश/अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं।

*एडी बैंकों और आरओ को शक्तियों का प्रत्यायोजन : विदेशी निवेश लेनदेन से संबंधित देरी की रिपोर्टिंग के लिए विलंब जमा शुल्क- मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी)*

V.31 उदारीकरण की भावना को ध्यान में रखते हुए, और व्यापार करने में आसानी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) विनियम, 2022 में विलंब जमा शुल्क (एलएसएफ) की अवधारणा को शुरू किया गया है, जिसे आरओ स्तर पर लागू किया गया है। जिसमें सात आरओ, अहमदाबाद, बेंगलूर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली को लिया गया। इसके बाद, 26 अगस्त, 2022 को विदेशी निवेश लेनदेन में एलएसएफ की गणना पर एक विस्तृत एसओपी और मार्गदर्शन नोट जारी किया गया।

**प्रमुख पहल**

*विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) विनियम, 2015 की व्यापक समीक्षा*

V.32 विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) विनियम, 2015, 2 मार्च 2015 को जारी किए गए थे। हालांकि, आईएफएससी प्राधिकरण (आईएफएससीए) की स्थापना

आईएफएससी प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत की गई है। परिणामस्वरूप, उक्त विनियमों के कई प्रावधान अनावश्यक हो गए हैं। तदनुसार, विनियमों की व्यापक समीक्षा की गई और फेमा के तहत संशोधित अधिसूचना का मसौदा, साथ ही साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम के तहत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना को अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार के पास भेज दिया गया है।

*भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा श्रीलंका सरकार को भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत सावधि ऋण - आईएनआर में श्रीलंका के साथ चालू खाता लेनदेन का निपटान*

V.33 एसबीआई और श्रीलंका सरकार के बीच 1.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सावधि-ऋण समझौते के एक भाग के रूप में किए गए श्रीलंका को भारतीय निर्यात के निपटान की सुविधा के लिए, ऐसे लेनदेन को 19 मई, 2022 से लागू एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) तंत्र के बाहर भारतीय रुपये में निपटाने की अनुमति दी गई है।

V.34 इसके अलावा, 8 जुलाई, 2022 को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया गया है कि श्रीलंका के साथ व्यापार लेनदेन सहित सभी पात्र चालू खाता लेनदेन अगली सूचना तक एसीयू तंत्र के बाहर किसी भी अनुमत मुद्रा में निपटाए जाएंगे।

*भारत अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईएक्स) के माध्यम से आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित योग्य जौहरियों द्वारा स्वर्ण आयात*

V.35 विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के अनुसार, योग्य जौहरियों (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण – आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित) को भारत के अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स), नामित एजेंसियों (डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित) और नामित बैंकों (रिजर्व बैंक द्वारा स्वर्ण आयात के लिए अधिसूचित) के माध्यम से हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोड के आधार पर विशिष्ट भारतीय व्यापार

वर्गीकरण (आईटीसी) के तहत स्वर्ण आयात करने की अनुमति है। 25 मई, 2022 से प्राधिकृत बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे योग्य जौहरियों (आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित) को विशिष्ट शर्तों के अधीन आईएफएससी में आईआईबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण आयात करने में सक्षम बनाने के लिए अग्रिम भुगतान भेजने की अनुमति दें।

*आईएनआर में पारदेशीय भुगतान के लिए कार्यनीति*

V.36 देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिचालन दक्षता में सुधार के लिए एक कुशल पारदेशीय भुगतान और निपटान प्रणाली के निर्माण के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सुधार कार्ययोजना के एक भाग के रूप में, रिजर्व बैंक ने 11 जुलाई 2022 को बैंकों को एक परिपत्र जारी करने के माध्यम से घरेलू मुद्रा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार भुगतान के लिए एक फ्रेमवर्क का परिचालन किया। यह भारतीय बैंकों और आईएनआर को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला का एक व्यापक अभिन्न अंग बनने में सक्षम करेगा।

V.37 बढ़ते विदेशी व्यापार और हालिया भू-राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए, व्यापार भुगतान और आईएनआर में निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा तंत्र में एक पूरक प्रणाली की खोज की जा रही है। पारदेशीय व्यापार के लिए आईएनआर के उपयोग को प्रोत्साहित करने और भारतीय निर्यात को और बढ़ाने के लिए इस प्रणाली को तैयार किया जा सकता है, जिससे अतिरिक्त रोजगार और आय हो जाती है।

V.38 जुलाई 2022 में पेश किया गया तंत्र आईएनआर में निर्यात / आयात के भुगतान और निपटान को करने, चालान बनाने और प्रभावी करने के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था है जो और मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में व्यापार भुगतान और निपटान की वर्तमान प्रथा के साथ सह-अस्तित्व में रहेगी। यह परिकल्पना की गई है कि आईएनआर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निपटान एक स्वैच्छिक और क्रमिक सिद्धांत के अनुसार हो सकता है और व्यापारिक भागीदारों के पास भी मौजूदा व्यवस्था का उपयोग करने का विकल्प होना चाहिए। लाभ दो गुना हैं: (i) यह राष्ट्रीय मुद्राओं (आईएनआर और

भागीदार देश की मुद्रा) के माध्यम से पूर्ण या आंशिक व्यापार लेनदेन के निपटान के माध्यम से विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण के मामले में दोनों देशों के लिए एक पारस्परिक रूप से लाभकारी तंत्र होगा। आईएनआर और भागीदार देश की मुद्रा में भुगतान और निपटान बचाव और रूपांतरण जैसी लागतों को कम करेगा; और (ii) विशेष रूप से *वास्ट्रो खातों* में अधिशेष रूप से शेष का उपयोग भागीदार देशों के बीच पारस्परिक व्यवस्था पर अन्य लाभकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

*बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति - उदारीकरण के उपाय*

V.39 विदेशी मुद्रा अंतर्वाह के स्रोतों में और विविधता लाने और उनका विस्तार करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 6 जुलाई 2022 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, 'विदेशी मुद्रा प्रवाह के उदारीकरण' पर स्वतः मार्ग के तहत ईसीबी सीमा को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अस्थायी रूप से इसके समकक्ष प्रति वित्तीय वर्ष 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और निवेश-ग्रेड रेटिंग के उधारकर्ताओं के लिए 100 आधार अंकों (बीपीएस) की समग्र लागत सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी। ये अस्थायी उपाय 31 दिसंबर 2022 तक उठाए गए ईसीबी के लिए उपलब्ध थे। तदनुसार, फेमा 3 (आर) [विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधार और ऋण) विनियम, 2018] में आवश्यक संशोधन करने के बाद, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों को

अधिसूचित किया गया था। दिशानिर्देशों की समीक्षा के बाद, अगस्त से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान 15.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के नए ईसीबी समझौते किए गए, जिनमें से 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर अस्थायी रूप से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की स्वचालित मार्ग के तहत बढ़ी हुई सीमा के तहत संपन्न हुए। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान, 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 0.1 मिलियन यूरो के ईसीबी समझौते भी निवेश-श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए प्रदान की गई संशोधित समग्र लागत सीमा पर संपन्न हुए।

*विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत देर से रिपोर्ट करने के लिए विलंब जमा शुल्क*

V.40 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत देरी से रिपोर्ट करने के लिए विलंब जमा शुल्क (एलएसएफ) की अवधारणा पेश की गई थी। एलएसएफ को क्रमशः 7 नवंबर 2017, 16 जनवरी 2019 और 22 अगस्त 2022 से प्रभावी विदेशी निवेश (एफआई), ईसीबी और विदेशी निवेश (ओआई) से संबंधित लेनदेन के लिए पेश किया गया था। प्रकार्यों में एलएसएफ लगाने में एकरूपता लाने के लिए, ओआई-संबंधित लेनदेन के लिए एक समान मैट्रिक्स के तर्ज पर एलएसएफ की गणना के लिए, जहां भी फेमा के तहत लागू हो, शुरू किया गया (बॉक्स V.3)।

### बॉक्स V.3

#### एक नई सीमापार निवेश (ओआई) व्यवस्था का परिचालन

उदारीकरण की भावना को ध्यान में रखते हुए और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार और रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत प्रक्रियाओं को उत्तरोत्तर सरल बना रहे हैं और नियमों और विनियमों को युक्तिसंगत बना रहे हैं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम एक नई विदेशी निवेश व्यवस्था के परिचालन के साथ उठाया गया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) विनियम, 2022 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2004, और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण और अंतरण) विनियमों 2015 के अधिक्रमण

में अधिसूचित किया गया है। 22 अगस्त 2022 को जारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) निदेश, 2022, समय-समय पर संशोधित 1 जनवरी 2016 के मास्टर निर्देश का स्थान ले चुका है। नई व्यवस्था व्यापक आर्थिक गतिविधि को शामिल करने के लिए भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा विदेशी निवेश के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क को सरल बनाती है और विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता को काफी कम करती है। इसके परिणामस्वरूप अनुपालन बोझ और संबंधित अनुपालन लागत कम होगी।

(जारी..)

नए नियमों और विनियमों द्वारा लाए गए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सारांश नीचे दिया गया है:

- 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेश', 'निवल मालियत', 'उप-अनुषंगी संस्था' आदि जैसी विभिन्न परिभाषाओं के संबंध में बढ़ी हुई स्पष्टता ;
- राष्ट्रीय हित के क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सुविधा के लिए 'कार्यनीतिक क्षेत्र' की अवधारणा का परिचय;
- भारत में निवासी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी जांच एजेंसी/नियामक निकाय द्वारा जांच के मामले में, विदेशी निवेश/विनिवेश के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी की आवश्यकता को संबंधित एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के साथ बदल दिया गया;
- विलंबित रिपोर्टिंग को रिकॉर्ड में लेने के लिए 'विलंब जमा शुल्क (एलएसएफ)' का एक तंत्र शुरू किया गया;

- दूसरी या उप-अनुषंगी संस्था' (एसडीएस) को या उनकी ओर से गारंटी जारी करना स्वचालित मार्ग के तहत लाया गया;
- मूल्य निर्धारण और अन्य दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन घाटे में चल रही विदेशी संस्थाओं के लिए विनिवेश के कारण बड़े खाते में डालने की अनुमति बिना किसी सीमा के दी गई;
- लाभप्रदता मानदंड के अधीन गैर-वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं को वित्तीय सेवा क्षेत्र (बीमा और बैंकिंग को छोड़कर) में निवेश करने की अनुमति देना; और
- किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार मूल्यांकन के लिए निवेश/विनिवेश के लिए मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों में लचीलापन लाया गया।

स्रोत : आरबीआई।

रूपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के तहत विदेशों से आने वाले बिल भुगतान को संसाधित करने के लिए भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को सक्षम बनाना

V.41 जैसा कि 5 अगस्त 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया, बीबीपीएस जो विदेशों से आने वाले बिल भुगतान को संसाधित करने के लिए मानक प्लैटफॉर्म है, को सक्षम बनाने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि रुपये आहरण व्यवस्था (आरडीए) के तहत प्राप्त विदेशी आवक प्रेषण को, बीबीपीएस के माध्यम से कुछ शर्तों के अधीन, बिलर (लाभार्थी) के ग्राहक को जानें (केवाईसी) अनुपालन बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना है। यह अनिवासी भारतीयों को भारत में उनके परिवारों की ओर से उपयोगिता, शिक्षा और अन्य बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा।

भारत में विदेशी निवेश – एफआईआरएमएस पोर्टल पर एकल मास्टर फॉर्म (एसएमएफ) में रिपोर्टिंग का युक्तिकरण

V.42 भारत में विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग के लिए 1 सितंबर 2018 को एक ऑनलाइन विदेशी निवेश रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (एफआईआरएमएस) शुरू की गई थी। तदनुसार, निवेश प्राप्तकर्ता कंपनियों और प्राधिकृत बैंकों सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, 5 जनवरी 2023

से फॉर्मों की रिपोर्टिंग की स्वतः पावती और देर से जमा शुल्क (एलएसएफ) की ऑनलाइन गणना की प्रणाली शुरू करने के लिए एफआईआरएमएस पोर्टल को नया रूप दिया गया। देश में विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे आसान बनाने की दृष्टि से प्रणाली को बदला गया था।

चालू सॉफ्टवेयर परियोजनाएं, जैसे, स्पेक्ट्रा और एपी कनेक्ट

V.43 प्राधिकृत व्यक्ति (एपी) कनेक्ट को 22 दिसंबर 2022 से पायलट गो-लाइव आधार पर परिचालित किया गया है। बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापार क्रेडिट रिपोर्टिंग और अनुमोदन (स्पेक्ट्रा) के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के संबंध में, यह कार्यान्वयन के एक उन्नत चरण में है।

### 2023-24 के लिए कार्यसूची

V.44 2023-24 के लिए विभाग की कार्यनीति उपर्युक्त सभी पहलों को समेकित करने और आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। आगे देखें तो, यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित रहेगा कि फेमा ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क उभरती समष्टिआर्थिक वातावरण की जरूरतों के अनुरूप है। इसके अलावा, बेहतर डेटा प्रबंधन और अनुपालन की लागत में कमी के इरादे से शक्तियों के प्रत्यायोजन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के युक्तिकरण के माध्यम से एपी की भूमिका को समृद्ध करने के प्रयास किए जाएंगे।

तदनुसार, विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित कार्यनीतिक कार्य योजना तैयार की है:

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत कंपाउंडिंग कार्यवाही नियमों की समीक्षा (उत्कर्ष 2.0);
- फेमा के तहत एपी के प्रमाणीकरण फ्रेमवर्क की समीक्षा (उत्कर्ष 2.0 );
- संशोधित एलआरएस की अधिसूचना (उत्कर्ष 2.0 );
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (प्राप्ति और भुगतान पद्धति) विनियम, 2016 पर विनियमों का युक्तिकरण (उत्कर्ष 2.0);
- अनिवासियों के रुपया खातों से संबंधित दिशा-निर्देशों की समीक्षा (उत्कर्ष 2.0);
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान माध्यम और गैर-ऋण लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियम, 2019 का युक्तिकरण;
- संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II के लिए पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क की समीक्षा;
- गारंटी विनियमों का युक्तिकरण; और
- व्यापार दिशानिर्देशों का युक्तिकरण/सरलीकरण (उत्कर्ष 2.0)।

## 5. निष्कर्ष

V.45 रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान बाजार में अस्थिरता को नियंत्रित करने, बाजार में व्यवस्थित स्थिति सुनिश्चित करने और बाजार की अपेक्षाओं को स्थिर रखने के लिए प्रमुख बाजार खंडों के आगे के विकास पर अपना ध्यान बनाए रखते हुए विकट वैश्विक प्रभाव विस्तार के बावजूद सक्रिय कदम उठाए। चलनिधि की स्थिति को समायोजन में कमी करने की दिशा में मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के साथ उन्हें संरेखित करने के लिए संशोधित किया गया था। रिजर्व बैंक ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों पर अंकुश लगाने के लिए विनियामक पहल भी की। यह अनुपालन बोझ को कम करने पर जोर देने के साथ अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के साथ विनियामक फ्रेमवर्क को संरेखित करने के अपने प्रयासों के साथ जारी रहा। आगे देखें तो, रिजर्व बैंक नए जोखिमों पर नज़र रखना जारी रखेगा, उभरते अवसरों का आकलन करेगा, और प्रणालीगत जोखिम को कम करने और बाज़ार पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि, सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा बाजार और मुद्रा के सारे पहलू को शामिल ने वाले नियमों को और मजबूत करने के लिए बाजार प्रतिक्रिया प्राप्त करेगा। चलनिधि परिचालन मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप बना रहेगा, जबकि विदेशी मुद्रा परिचालन रुपये की विनिमय दर में सुव्यवस्थित गति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देशित होगा।